

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

राकेश कुमार छाजेड़ बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 4817/1996 अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान.

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री एम.सी. शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

श्री एस.एस. राघव, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी क्रम-3.

न्यायालय द्वारा-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

यद्यपि प्रार्थी ने जो आवेदन पत्र (प्रदर्श-1) दिनांक- 28.01.1988 को प्रस्तुत किया था वह रिको भूमि का निस्तारण नियम, 1979 द्वारा निर्दिष्ट प्रफोर्मे में नहीं है, किन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक- 28.01.1988 को जिलाधीश, अजमेर ने आदेश दिनांक- 25.10.1989 द्वारा रिको को अग्रेषित करते हुए निर्देश दिया था कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता एवं वरियता के आधार पर निस्तारित करें। मैं नियमों की

तकनीकी में जाना उचित नहीं समझता, किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने 28.01.1988 को प्रस्तुत किया था उसका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना न्यायोचित होगा। वैसे भी रिको ने जिलाधीश, अजमेर को यह सूचित नहीं किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस कारणों से विचार नहीं किया जा रहा है कि वह निर्धारित प्रफोर्म में नहीं है। मेरा यह मानना है कि जहाँ पर तकनीकी और सारभूत न्याय एक-दूसरे के सामने खड़े हो वहाँ पर सारभूत न्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा तकनीकी को उपेक्षित किया जाना चाहिए। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक- 28.01.1988(प्रदर्श-1) के अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90 (क) सपठित राजस्थान भू- राजस्व [कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग] नियम, 1963 के नियम-3 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रतिपक्षी रिको ने प्रस्तुत किए रिट याचिका के उत्तर की मद संख्या-10 में यद्यपि आपत्ति प्रस्तुत की है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिको भूमि का निस्तारण नियम, 1979 द्वारा निर्दिष्ट प्रफोर्म में प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु उसने इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी थी और न ही ऐसा कोई प्रलेख अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया है कि उसे प्रतिपक्षी रिको की ओर से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उसे कहा गया हो कि वह रिको भूमि का निस्तारण नियम, 1979 द्वारा निर्दिष्ट प्रफोर्म में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करे।

प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रिको (प्रतिपक्षी क्रम-3) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक- 28.01.1988 (प्रदर्श-1) का निस्तारण आज से तीस दिन के भीतर आवश्यक रूप से कर देगी तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का

निस्तारण करते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखा जावेगा कि प्रार्थी ने अपना आवेदन पत्र 28.01.1988 को प्रस्तुत कर दिया था। उक्त निर्देश के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेंगे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस